# भारत का अंतरिम केंद्रीय बजट 2019-20 की मुख्य विशेषताएं





# म्ख्य हाईलाइट्स अंतरिम केंद्रीय बजट 2019-20

प्रिय पाठकों,

यह पीडीएफ फाइल 2019-2020 में वित्त मंत्री पियूष गोयल द्वारा 1 फरवरी 2019 को पेश किये गए अंतरिम बजट के अध्ययन के लिए एक सम्पूर्ण अध्ययन स्त्रोत है| बजट से संबंधित यह दस्तावेज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे- एसएससी, आईबी, रेलवे एवं अन्य सरकारी नौकरी से संबंधित परीक्षाओं के अध्ययन के लिए प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है|

#### अंतरिम केंद्रीय बजट 2019-20

अंतरिम बजट 2019-20 संसद में 1 फरवरी 2019 को केन्द्रीय मंत्री पियूष गोयल(वित्त मंत्री, रेल एवं कोयला मंत्री, कॉर्पोरेट मंत्री) द्वारा पेश किया गया। यह बजट वर्तमान मोदी सरकार का इस संसदीय अवधि का 6 वाँ एवं अंतिम बजट है।

#### अंतरिम बजट के बारे में:

- अंतरिम बजट एक अस्थायी वित्तीय दस्तावेज होता है जो व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं को सामान्य बजट से कम समय अंतराल (एक वर्ष से कम समय) के व्ययों से संबंधित होता है|
- अंतरिम बजट में भी पूर्ण बजट की ही तरह पूर्ण वित्तीय व्यौरा दिया जाता है।
- एक सामान्य बजट की ही तरह अंतरिम बजट में भी पूरे बजट के लिए वित्तीय अन्मान प्रस्त्त किये जाते हैं।

#### अर्थव्यवस्था एवं वित

#### 1. राजकोषीय घाटा-अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे को 3.4 % पर आंकलित किया

- अंतरिम बजट में राजकोषीय बजट को संशोधित कर 3.4% कर दिया गया।
- पूंजीगत व्यय 3.36,292 लाख करोड़ है|
- 2018-19 के संशोधित व्यय अनुमान से व्यय के 2019-20 में 13% तक बढ़ जाने का अनुमान है|
- 2. चाल् खाता घाटा 2.5% रहने का अन्मान है|
- 3. पिछले पांच वर्षों में प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत लगभग 34 करोड़ बैंक खाते खोले गए
- 4. वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था द्निया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है|
- कर लाभ
- ्वयक्तिगत करदाता जिनकी करयोग्य आय 5 लाख तक है उन्हें अब आयकर देने की आवश्यकता नहीं है। नोट-

SSC 2019 Plus Pack ATTEMPT MOCK



- सरकार ने 5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट का प्रस्ताव किया है, जिसका अर्थ है कि 5 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को करों का भुगतान करने से छूट दी जाएगी, लेकिन उसी का दावा करने में विफल रहने के बिना रिटर्न दाखिल करना होगा।
- वर्तमान में लागू आयकर की दरों को ही आगे जारी रखा जाएगा.
- 6. वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए बेतनभोगी व्यक्तियों के लिए मानक कर कटौती को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया।
- 7. बैंक एवं पोस्ट ऑफिस जमा पर पर TDS थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर 10,000 से 40,000 रुपये कर दिया।
  - घर किराए से संबंधित आय पर टीडीएस की सीमा को 1.8 लाख से बढ़ाकर 2.4 लाख कर दिया गया।
- 8. पूंजीगत लाभ पर रोल ओवर को अब दो आवासीय घरों में निवेश तक बढ़ा दिया गया। इस लाभ को पूरे जीवनकाल में केवल एक बार लिया जा सकता है।

#### मुद्रा योजना -

- 9. वित्त मंत्री ने बताया कि मुद्रा योजना के अंतर्गत 16.53 करोड़ लॉन वितरित किये गए, बाद में उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना के तहत कुल 7.23 लाख करोड़ की धनराशि वितरित की गयी।
- 10. कुल व्यय के मुकाबले राजस्व व्यय 2018-19 में 24,57,235 करोड़ के मुकाबले 2019-20 में 27,84,200 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा।
- 11. कुल 3,26,965 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी जोकि लगभग 13.30% के बराबर है। यह वर्तमान में कम मुद्रास्फीति को देखते हुए अधिक वृद्धि को दर्शाता है।



- 12. FRBM एक्ट के आधार पर भारत सरकार को अपने कर्ज और जीडीपी अनुपात को 2024-25 तक 40% से नीचे लाना है|
- 13. ग्रैच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया।

SSC 2019 Plus Pack



भारत सरकार ने ग्रैच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया|

#### रेलवे

- 14. वर्तमान बजट में रेलवे को Rs. 64587 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया|
- 15. वन्दे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन 18) गति, सेवा और स्रक्षा प्रदान करेगी और मेक इन इंडिया को एक नयी दिशा देगी।
- 16. ब्रोड गेज रेलवे पथों पर सभी मानवरहित रेलवे क्रोसिंग्स को हटा दिया गया है|
- 17. रेलवे का क्ल पूंजीगत व्यय 1,58,658 करोड़ रुपये का है|
- 18. ऑपरेटिंग अनुपात वर्तमान के 2017-18 के 98.4% के मुकाबले 2018-19 में 96.2% और 2019-20 (बजट अनुमान) में 95% तक होने की संभावना है|

## आधारभूत संरचना

19. भारत 27 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से पूरी दुनिया का सबसे तेज राजमार्ग विकसित करने वाला राष्ट्र है। बाद में वित्त मंत्री ने बताया कि ऐसे प्रोजेक्ट जो वर्षों से अटके हुए थे अब पूरे हुए हैं।

#### योजनाएँ

#### 20. सरकार ने किसानों के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की

- योजना का उद्देश्य ऐसे किसान जिनके पास छोटे जोत की जमीन है। पूरे देश में 12.56 करोड़ सीमान्त और छोटे किसान है जिनके पास 2 हेक्टेयर(5 एकड़) भूमि से भी कम जोतें हैं।
- बजट प्रावधान इस योजना के लिए बजट में Rs 75, 360 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है|
- आय सहायता इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 6 हजार रुपये की आय सहायता देने का प्रावधान है।



# मुख्य बिंद्:

मछली पालन एवं पशुपालन करने वाले किसानों को 2 प्रतिशत तक की व्याज छूट मिलेगी।

SSC 2019 Plus Pack



- प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली लॉन पर 2 प्रतिशत तक की व्याज छूट मिलेगी और कृषि ऋण का समय पर लॉन चुका देने पर अतिरिक्त 3% तक की छूट का प्रावधान है।
- भ्गतान तीन किस्तों में किया जाएगा।
- यह किसानों को कर्ज के चक्र में फंसने से एवं बीज एवं खाद खरीदने में मदद करेगा|

नोट:

• बजट में पेश यह योजना तेलंगाना सरकार की रायथू बंधू योजना का संशोधित रूप है जो किसी भी भूमि जोत वाले किसान को 8 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से वितीय मदद का प्रावधान करती है|

# 21. मेगा पेंशन योजना- प्रधान मंत्री श्रम योगी मंधन योजना

### मुख्य बिंद्

- इस योजना के लिए कुल 500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है|
- असंगठित क्षेत्र में नौकरी करने वालों के लिए 100 रुपये प्रति महीने के योगदान पर 60 वर्ष की उम्र के पश्चात 3 हजार रुपये प्रति महीने पेंशन का प्रावधान है।
- यह योजन असंगठित क्षेत्र के लगभग 10 करोड़ कामगारों के लिए उपयोगी होने के साथ ही अगले पाँच वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन स्कीम बन जायेगी।
- यह योजना वर्तमान वर्ष से लागू की जायेगी|
- 22. MGNREGA MGNREGA के लिए 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
- 23. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए बजट में 19,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- 24. पिछले पाँच वर्ष में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 1.53 crore आवासों का निर्माण किया गया।
- 25. PM उज्ज्वला योजना: इस योजना के तहत अब तक 6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए
  - स्वच्छ ईंधन एवं स्वास्थ्य प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरित किये गए- वित्त मंत्री पियूष गोयल

# 26. वन रैंक वन पेंशन स्कीम(OROP) -

- OROP स्कीम के तहत अब तक 35000 करोड़ रुपये वितरित किये गए|
- 27. इंटीगरेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के लिए बजटीय प्रावधान को 2018-19 के 23,357 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2019-20 में 27,584 करोड़ रुपये कर दिया गया।

#### स्वास्थ्य क्षेत्र

# 28. आयुष्मान भारत योजना

- स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लगभग 10 लाख लोगों का इलाज किया गया।
- इस स्कीम के लागू होने से नागरिकों ने लगभग 3 हजार करोड़ की घरेलु बचत की

SSC 2019 Plus Pack



#### 29. 21 AIIMS में से 14 इस सरकार के अंतर्गत स्थापित किये गए। 22 वाँ AIIMS हरियाण में स्थापित किया जाएगा।



कृषि एवं किसान

# 30. राष्ट्रीय कामधेन् आयोग स्थापित किया जाएगा

उद्देश्यः गौ धन के स्थाई अनुवांशिक उन्नयन एवं गौधन के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रावधानों की घोषणा की गयी|

- यह आयोग गौधन से संबंधित कानूनों और कल्याण योजनाओं से संबंधित प्रावधानों को भी देखेगा।
- भारत द्निया में डेरी उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है|

# 31. राष्ट्रीय गोकुल मिशन - इस मिशन के अंतर्गत 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

 स्वदेशी नस्लों और उनके विकास साथ ही उनके अनुवांशिक उन्नयन और उत्पादकता बढ़ाने एवं रोगों के उचित निदान से संबंधित दवाओं के वितरण से संबंधित प्रावधान किये गए है।

#### रक्षा

32. रक्षा क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक बजटीय आवंटन।

#### संगठित क्षेत्र

#### 33. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) - भविष्य निधि सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया

- वेतनभोगी लोगों के परिवार की सुरक्षा के लिए सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया(कर्मचारी के निधन की स्थिति में)
- 34. पिछले पाँच वर्ष में EPFO की सदस्यता 2 करोड़ का इजाफा हुआ है इससे अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण का संकेत मिलता है|
  - पिछले पाँच वर्षों में सभी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन में 42% की बढ़ोत्तरी हुई है जोकि सर्वाधिक है, वित्त मंत्री ने कहा।
  - ESI कवर की सीमा 21,000 हजार रुपये तक बढ़ा दिया गया है|
  - न्यूनतम पेंशन को भी 1 हजार रुपये कर दिया गया।

#### विविध

SSC 2019 Plus Pack



- 35. खानाबदोश एवं अर्द्ध खानाबदोश सम्दायों के लिए एक नए आयोग का गठन किया जाएगा|
- 36. भारतीय सिनेमेटोग्राफी एक्ट में एंटी-केम्कोर्ड नियमों को जोड़ा जाएगा ताकि बोलीवुड फिल्मों की पायरेसी को रोका जा सके।
- 37. मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय फिल्मकारों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेन्स की व्यवस्था की जायेगी|
- 38. भारत की स्थापित सौर क्षमता में पिछले पाँच वर्षों में 10 गुना वृद्धि हुई है|
- 39. उत्तर पूर्व के लिए 58,166 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ रिकॉर्ड आवंटन
- 40. डिपार्टमेंट ऑफ़ इंडस्ट्रियल पालिसी एंड प्रमोशन के नाम को बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ़ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड कर दिया जाएगा|
- 41. अंतरिम बजट में 2030 के लिए 10 सूत्री विजन
  - (i) अगली पीढ़ी आधारिक संरचना
  - (ii) डिजिटल भारत
  - (iii) इलेक्ट्रिक वाहनों पर यात्रा करता ह्आ प्रदुषण मुक्त भारत
  - (iv) ग्रामीण उद्योगीकरण का विस्तार
  - (v) शुद्ध पेयजल के साथ स्वच्छ नदियाँ
  - (vi) सम्द्र तट की सफाई एक साथ नीली अर्थव्यवस्था का दोहन
  - (vii) एक भारतीय को सही जगह स्थापित करना
  - (viii) खाद्य, खाद्यानों के निर्यात और जैविक खाद्यानों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना
  - (ix) स्वास्थ्य भारत, एक संकट मुक्त स्वास्थ्य सेवा और व्यापक कल्याण प्रणाली
  - (x) अधिकतम प्रशासन



SSC 2019 Plus Pack

# SSC 2019 Plus Pack

- 1.600+ Mock Tests on the Latest Exam Pattern
- 2. Available in Hindi & English
- 3. All India Rank & Performance Analysis
- 4. Detailed Explanation of Solutions
- 5. Topic-wise Tests & Video Courses
- 6. Available on Mobile & Desktop

